

प्रगति पथ पर
गतिमान राजस्थान

शहरी विकास को नई रफ्तार - आधुनिक राजस्थान की नई पहचान

मजबूत सड़कें • सुगम यातायात • बेहतर ड्रेनेज • आधुनिक सीवरेंज • सुरक्षित सबवे • बेहतर मेडिकल सुविधाएं • श्रमिक कल्याण • स्वच्छ एवं हरित परिवहन

राजस्थान के शहरों को मिल रही ₹2,340 करोड़ की सौगातें
941 कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के

1 लाख 32 हजार 421 लाभार्थियों को ₹154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि की डीबीटी

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में जयपुर को बड़ी सौगात

लोकार्पण

RUHS जयपुर : 128-स्लाइस CT स्कैन मशीन

जनाना चिकित्सालय, चांदपोल : नवीन आईपीडी टावर

SMS अस्पताल :

आयुष्मान टावर अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

RUHS जयपुर :

1.5 टेस्ला MRI मशीन तथा नवीन स्नातक छात्रावास

जयपुर जिले में झोटवाड़ा के अभयपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वा. केन्द्र, रेहलाना का निर्माण कार्य

शिलान्यास

जयपुर जिले के झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय

पीएम ई-बस योजना

71 ई-बसों का शुभारंभ

जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से
तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर से 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ



वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश हैं या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं?

कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था।

यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंतरे पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है।

इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचैनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादाल्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझा लिया

गया और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके। मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कतर में रहने वाले भारतीय यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रেমिटेंस)

- यह सेवा डाक विभाग तथा कतर डाक सहित संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक सहित, अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज

जयपुर, 17 अगस्ता। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र की शुरुआत से पहले, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अध्यक्ष देवनानी की अध्यक्षता में होने वाली यह सातवीं सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली,

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचैतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचैतक प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है?

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।

- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है। “दिमागी नक्सल” का तंज इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को रा्ट्-

विरोधी या वैचारिक रूप से दृष्टित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है। एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

की यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनेरेशन जी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है।

कॉकरोच जन्मा पार्टी के जैनेरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मुलौ कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है। सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शहजाद पूनावाला ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दिया

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन से अनुरोध किया है कि इस बार उनके इस्तीफे को स्वीकार

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सख्त निर्देश दिये।

अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर सख्त रुख अपनाने हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने पान मसाला ब्रांड का प्रचार, कानून से खिलवाड़ की एक और मिसाल

महाराष्ट्र सरकार ने विमल इलायची के प्रचार के लिए बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एक्शन लेकर “सरोगेट एडवर्टिज़मेंट” के खेल को सुर्खियों में ला दिया है

- “सरोगेट” यानि छद्म विज्ञापन वे विज्ञापन हैं, जिनमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है, जैसे विमल गुटखा के प्रचार के लिए विमल इलायची का विज्ञापन किया जाता है।
- भारत में तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून रोक है और इस कानून में बाद में ऐसे नियम भी जोड़ दिए गए, जिनमें तंबाकू उत्पाद ब्रांड के प्रचार के लिए अन्य उत्पाद का प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून की गाइडलाइन्स में भी “सरोगेट” विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्मी हस्तियों पर की गई कार्यवाही सैलिब्रिटी विवाद बन कर न रह जाए, यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि, यह मुद्दा इस विवाद का समाधान कर सकता है कि क्या किसी वैध उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।

वाली कंपनियाँ इलायची, माउथ फ्रेशनर और अन्य उत्पादों जैसे ब्रांड एक्सटेंशन के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखती हैं,

जबकि उक्त उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पहले से ही एक

मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.पी.टी.ए.), 2003 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

इस कानून के तहत बाद में बनाए गए नियम अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर भी रोक लगाते हैं। इनमें तम्बाकू उत्पाद के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल अन्य सामान

सेवाओं या कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना भी शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्यवस्था भी इसमें एक और स्तर जोड़ती है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की 2022 की गाइडलाइंस उन वस्तुओं और सेवाओं के सरोगेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती हैं, जिनके विज्ञापन पर पहले से प्रतिबंध या रोक है। फिर भी इन नियमों को लागू करना मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बचाव (डिफेंस) सीधा है: विज्ञापन पूरी तरह से वैध उत्पाद के लिए है। इस बचाव की अदालतों में परीक्षा हो चुकी है। विमल इलायची से जुड़े एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारश्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीजल प्रबंधन में नए कीर्तिमान
जल समृद्ध हो रहा राजस्थान₹91,000 करोड़ की लागत से
राम जल सेतु लिंक परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- 4.98 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- 17 जिलों को पेयजल-जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर

₹34,102 करोड़ की
यमुना जल परियोजना

शेखावाटी को वर्षों बाद जल

32 वर्षों का इंतजार पूरा

चूरु, सीकर, झुंझुनू - भरपूर पानी



राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर

गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी-तंत्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के लिए राशि ₹5500 करोड़

लाभान्वित जिले - हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरु, बीकानेर, फलौदी

जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना-कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा

ब्राह्मणी-राणा प्रताप सागर- बनास लिंक

680 एमसीएम जल बनास नदी में अपवर्तन लाभान्वित जिले भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं डीग

₹2,500 करोड़

की अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना
से बांसवाड़ा के 338 गांवों में सिंचाई

देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खारी फीडर की जल संवहन क्षमता को दोगुना करने की लगभग ₹150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

₹7,355 करोड़ की

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं 1402 गांवों में पेयजल सुविधा

पाली एवं सिरौही में पेयजल आपूर्ति हेतु सेई एवं साबरमती बांधों का निर्माण कर जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागत ₹1,255.90 करोड़ है साथ ही, सेई बांध की टनल क्षमता बढ़ाने पर ₹65 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

माही बेसिन के अनास एवं सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम बांध, जयसमंद बांध के साथ साथ सोम-कमला-अंबा बांध के माध्यम से जवाई बांध एवं जालौर तक आपवर्तित करने का संकल्प
लाभान्वित जिले: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर एवं जोधपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने,



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कृषि लागत कम करने और ऊर्ध्व आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का

शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नितिन नबीन ... आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली

सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कार्यवाही कर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम किये

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

के ज़रिए समन्वित बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया। इसमें 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई

समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

कतर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से पन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए सत्र के सफल संचालन में सहयोग करेंगे।

शहजाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूनावाला ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

“दिमागी नक्सल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर खुद को संगठित किया है।

स्वष्ट रूप से, मोदी का यह संदेश वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज की आवाजों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है, जिन्हें भाजपा लंबे समय से “अर्बन नक्सल” कहती रही है।

इसमें असहमति, विशेषकर शासन, शिक्षा व्यवस्था की निफलताओं या हिंस्तुत्व की प्राथमिकताओं की आलोचना, को वैध राजनीतिक विरोध के बजाय माओवादी विद्रोह के वैचारिक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

क्रोएस ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस टिप्पणी को हताशा का पक्का संकेत बताया।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

■ **मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की**

■ **मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।**

छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगों मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दावाियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, परीक्षा में सफल अर्थार्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, “हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?”

जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

■ **नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।**

पुर्देशवरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रती सिंह बादल, लाल सिंह अग्र, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा, मंगलाल रावत को अनुसूचित जनजाति और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अनिल बलूनी को फिर मीडिया संयोजक बनाया गया है। आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक बनाया गया है। दीपक म्हरके को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को सिंह, मुर्गाका देव बर्मन, रोहन गुप्ता,

राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, संदीप पाठक, फांमोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, एम वेंकटेशन , राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अक्सर अपने आलोचकों को बदनाम करती है और बातें में उन्हीं की मांगों को अपना लेती है। उन्होंने इसके उदाहरण के रूप में जातीय जनगणना का हवाला दिया।

विपक्ष के अन्य नेताओं, जिनमें भाकपा के डी. राजा भी शामिल हैं, ने इस शब्द को असहमति को दर्शाते कर्त्ताकृत करने और सरकार को सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बताया है।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनावई के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाईस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनावई के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाईस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

‘अगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनावई के दौरान याचिकाकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने आरोप लगाया कि एयरलाईस जिस तरह से यात्रियों से शुल्क वसूल रही हैं, उसके लिए बनाए गए आधिकारिक नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है।

इस तरह, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस सिर्फ एक और सेलिब्रिटी विवाद बनकर न रह जाएं। वे एक ऐसे सवाल को सुनावई का मौका दे सकते हैं जो बरसों से बना हुआ है: कोई उत्पाद कानूनी हो सकता है, लेकिन क्या उसका विज्ञापन कानूनी तौर पर किसी ऐसी चीज के विज्ञापन के रूप में काम कर सकता है, जो खुद कानूनी नहीं है?

जब तक इस सवाल का जवाब एक स्पष्ट रेगुलेटरी टेस्ट के ज़रिए नहीं दिया जाता, तब तक सरोटेंट विज्ञापन की यह कानूनी खामी प्रतिबंधित ब्रांडों को बाज़ार में अपनी पहचान बनाए रखने का मौका देती रहेगी और उन्हें अपने उत्पाद को खुलेपन विज्ञापन करने की जरूरत भी पड़ेगी।